षोडश

बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार, तिथि 02 श्रावण, 1941 (श०)
24 जुलाई, 2019 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 04

(1)	पंचायती राज विभाग	02
(2)	ग्रामीण विकास विभाग	01
(3)	श्रम संसाधन विभाग	01
	कुल योग --	04

प्रशिक्षुओं का कोटा बढ़ाना

28. श्री मिथिलेश तिवारी--क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के शिक्षुता (संशोधन) नियम, 2015 के आलोक में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान संविदात्मक कर्मचारी सहित कुल कर्मचारी संख्या के न्यूनतम 2.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक की सीमा में शिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में औद्योगिक प्रतिष्ठानें की संख्या कम होने के कारण तथा आई0टी0आई0 उत्तीर्ण शिक्षुओं की संख्या ज्यादा होने के बावजूद अधिकतम 15 प्रतिशत के मानक के आधार पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा शिक्षुओं को प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के आई0टी0आई0 उत्तीर्ण शिक्षुओं के प्रशिक्षण हेतु राज्य में संचालित औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों की कुल संख्या के न्यूनतम 2.5 प्रतिशत के बदले 15 प्रतिशत तक शिक्षुओं को प्रशिक्षण दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनियमितता की जाँच

29. श्री ललित कुमार यादव--क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में ''हर घर नल का जल'' योजना के अन्तर्गत नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर तक पानी पहुँचाने का प्रावधान है किन्तु उक्त योजना के लिये निर्धारित मानको के विपरीत दरभंगा जिला के दरभंगा सदर प्रखंड के सोनकी पंचायत, मनीगाछी प्रखंड के गंगोली, कनकपुर एवं उजान पंचायत, दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड में औरंगाबाद जिला के गोह प्रखंड में तथा वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंड में मानक के अनुसार बोरिंग नहीं की जा रही है और न ही मानक स्तर के पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त जिला के साथ-साथ पूरे राज्य में इस योजना में की जा रही अनियमितता की जाँच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गरीबी का उन्मूलन

30. श्री समीर कुमार महासेठ--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 13 जुलाई, 2019 को प्रकाशित शीर्षक ''बिहार के 38 जिलों में 11 ऐसे जिनमें 10 में 6 लोग गरीब'' के आलोक में क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से जारी ग्लोबल मल्टीडाईमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्टस (एम0पी0आई0) की ताजा रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ है कि भारत में सबसे गरीब राज्य बिहार है और राज्य के 38 जिलों में से 11 जिले ऐसे हैं जिनमें 10 में से 6 लोग गरीब है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त 11 जिले उत्तर बिहार के हैं और इनमें भी विशेषकर अररिया व मधेपुरा में गरीबों की संख्या 10 में 7 है ;

(3) क्या यह बात सही है कि देश में 60 प्रतिशत से ज्यादा गरीब वाले कुल 640 जिले हैं, जिनकी कुल आबादी 4 करोड़ है जिसमें से 2,00,80,000 लोग बिहार के हैं ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य की गरीबी समाप्त करने के लिये कौन-सा कदम उठाने का विचार रखती है ?

पंचायत सरकार भवन का निर्माण

31. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी--क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि --

(1) क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारी को अपने पत्रांक 1442, दिनांक 4 जुलाई, 2019 द्वारा पत्र लिखकर निदेश दिया गया है कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण ग्राम पंचायत के मुख्यालय गाँव में ही बनाया जाये ;

(2) क्या यह बात सही है कि पंचायत सरकार भवन के लिये ग्राम पंचायत के वैसे मुख्यालय जहाँ सार्वजनिक अथवा सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, वहाँ पंचायत सरकार भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उस मुख्यालय गाँव में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

पटना :
दिनांक 24 जुलाई, 2019 (ई0) ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0 53(एल0ए0), 2019-20-डी0टी0पी0-500